Setting up of uniform Civil Courts

@1575. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for setting up uniform civil courts and family courts for bringing about justice and welfare to the vulnerable sections of society;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for not considering such a proposal?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) No proposal for setting up of uniform civil courts is under consideration of the Government. Family courts have been set up by the State Governments of Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu for speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs.

जे०जे० कालोनियों के आवंटितियों से धन कर और गृह कर का संग्रहण

1576. श्री सुरेन्द्र कुमार पटवालिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम जे०जे० कालोनी, सीलमपुर, तथा अन्य जे०जे० कालोनियों व पुनर्वास कालोनियों के आवंटितियों से धन कर/गृह कर वसूल करता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 285 का सरासर उल्लंघन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार दिल्ली नगर निगम द्वारा की जा रही इस अनियमितता को रोकने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार वसूल की गई कर राशि को वापस लौटाने और निम्न वर्ग के कल्याण के लिए उपाय करने का भी विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी नहीं, श्रीमन । दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम साक्षधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जे० जे० कालोनियों से केवल गृह कर की वसूली करता है । 1000 रु० की दर योग्य कीमत की आवासीय सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Supreme Court Bench in South India

1577. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a Bench of the Supreme Court in South India;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government will make any special arrangements for the speedy disposal of special leave petitions from South India?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is mainly the concern of the Supreme Court.

Advance Flood Forecasting Centres in Andhra Pradesh

1578. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of

@Preriously Unstarred Question 1288, transferred from the 3rd March, 1989.